

SHRI D. N. PATODIA : He has denied it only when the matter was brought to the notice of the House.

MR. SPEAKER : He has contradicted it here. Why he did not do it earlier is the point.

DR. V. K. R. V. RAO : I can answer that. I was out of station. I came only last night from a tour of Machlipatam, Vijayawada and other places.

MR. SPEAKER : He saw it last night.

So, you saw it only last night.

DR. V. K. R. V. RAO : I saw it only last night, and I could deny it only today.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Eight Minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATIONS BILL—Contd.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

If you will permit me, I just have one small point that I wanted to mention. Yesterday, while accepting amendment No. 172 by Shri K. Narayana Rao, I had mentioned a little alteration and sought the permission of the House to make that alteration, that this amendment should come after the word "Fails to subscribe." It is just shifting a few words back. It makes it more meaningful, but that seems to have escaped the attention of the Lok Sabha Secretariat. I hope you will agree to this change being made.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is just a drafting change. It is not a material change. I hope the House accepts it.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yesterday, I said I would just permit half an hour's discussion. The Minister of will just take 10 minutes for his reply.

श्री अश्वपुत्र नगी डार (गुडगांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि थर्ड रीडिंग स्टेज पर कुछ उपाय कहना प्रणया नहीं लगता है लेकिन इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि यह मेज 80 परसेंट कल्टीवेटर्स, किसान, पीजेंट्स और लेबरर्स लोगों के भले में लिए सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इस प्रबन्ध पर मैं उनसे सिर्फ हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना करना चाहूंगा :

"खिलौने देकर बहलाया गया है, व तमन्नाओं में जलझाया गया है।"

मेरा कहना यह है कि खाली जबानी जमा खर्च से किसानों का मसला हल होने वाला नहीं है। किसानों को वक्त पर ट्रैक्टर्स नहीं मिलते, वक्त पर उनको बीज नहीं मिलते, फटिलाइजर्स नहीं मिलते और न ही उन्हें वक्त पर कर्जा मिल पाता है। एक तो कर्जा वक्त पर नहीं मिलता है और मिलता भी है तो जैसे मेरे और भाइयों ने कहा किसानों को उसे हासिल करने में बड़ा खर्चा करना पड़ता है। किसान बेचारे इधर, उधर घबके खाते फिरते हैं। इसी तरह जब वह ट्रैक्टर्स लगाते हैं तब उनको कर्नैशन नहीं मिलता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जल्दी में ताकि पांच मिनट में मैं अपनी बात कह दूँ। जब मेनेजमेंट का सवाल उठा था उस वक्त तबज्जह दिखाई गई थी, और उन्होंने इन्कार कर दिया था इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि उन की पार्टी के जो लोग हार जाते हैं वह काबिलियत में कम होते हैं, मगर धाज तक देखने में नहीं आया कि जो कारपोरेशनों के चेयरमैन बन रहे हैं या पब्लिक सेक्टर के चेयरमैन बन रहे हैं, उनमें से कोई भी अपोजीशन का जीडर हो। चाहे वह कामत हो या कोई और हो। जो बड़े कांग्रेसी तसदीकनुवा लोग हैं वही धाये हैं। इससे डर पैदा होता है :

[श्री अब्दुल गनी डार]

जहां 656 करोड़ रुपया लगा हुआ है वहां किसी प्रायोजीशन वाले को नहीं लिया गया है हालांकि पब्लिक सेक्टर को हम भी पसन्द करते हैं और हमारे भाई भी पसन्द करते हैं। आज उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। वहां किसानों के लिये कोई ट्रैक्टर नहीं बनता, कोई और मशीन नहीं बनता, जो किसानों को फ्री दिया जा सके।

कल यहां 1 करोड़ और 5 करोड़ की बहस चल रही थी। लेकिन सिर्फ वेस्ट बंगाल का नुकसान कई करोड़ रुपयों का है। आप बिहार को छोड़िये, उड़ीसा को छोड़िये, गुजरात को छोड़िये, राजस्थान को छोड़िये, हरियाणा को छोड़िये, उनको जो नुकसान हुआ वह भलग है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मिनिस्टर साहब वाई सीरियस हैं और ईमानदार है तो यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये पब्लिक सेक्टर में भ्राममी भेजे जायें। मैंने अपनी पार्लियामेन्ट्री जिन्दगी में कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा जिसने कोई भी कामन सेंस की बात को कबूल किया हो। सिर्फ एक मिनिस्टर शिन्दे मैंने देखा जिसने ऐसा किया है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ही देखिये। कितनी ही माफूल बात क्यों न हो फाल्स प्रेस्टिज में फंसकर वह उसको नहीं मानते। मैं श्री पन्त को कांग्रेसुलेट करता हूँ कि वह किसानों की भलाई की बात करने जा रहे हैं। यह बात उनकी काबिले तारीफ है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसा पहले होता आ रहा है, अगर अब की भी वही हुआ तो इसका नतीजा खराब होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां तक मेनेजमेंट का सबाल है उस पर मिनिस्टर साहब जरूर तबज्जह देंगे और उनको मुकर्रर करते वक्त खूब ठोक बजा कर उनको लिया जायेगा। जो भी किसानों के हितैषी हों वह इस कारपोरेशन को चलायें और रिजर्व बैंक को भी चलायें।

मैं दो तीन दिनों के भीतर दूसरा भाई-भापेनर देने वाला हूँ जिससे अगर तक

सरकार की भांखें नहीं खुली तो अब खुल जायेंगी।

(श्री मन्त्री डार: कृष्णा नदी पर 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है जो अभी तक आधा प्रकृत्ये नही बना है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा।)

"कलहने देकर बहलियांगी हों नशादों में, आजादी हों।
मिराकना-ये के कथाली नयां जे खर्च से कसानों का संस्करण करने वाला है।
ये कसानों को क्वट पर थ्रु क्लिअर नही हलें। क्वट परान को बज नही हलें क्वट फंडिंग नही हलें।
नही हलें। और नही अखिल क्वट पर क्वट फंडिंग नही हलें।
नही हलें। और नही अखिल क्वट पर क्वट फंडिंग नही हलें।
को आसे क्वट फंडिंग नही हलें। और नही अखिल क्वट पर क्वट फंडिंग नही हलें।
कसान बिचारे ओहरो ओहरो क्वट फंडिंग नही हलें।
ओहरो ओहरो क्वट फंडिंग नही हलें।

एक बात है और क्या बताऊं कि मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।
कह दो। जब सिविल क्वट फंडिंग नही हलें।
ने अंकार कर दिया है। मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।
पार्टी के जो लोग जा रहे हैं वे क्वट फंडिंग नही हलें।
दिक्खें नही हलें।
सिक्कुर के बिचारे ओहरो ओहरो क्वट फंडिंग नही हलें।
पहले वे क्वट फंडिंग नही हलें।
लगे हलें।
दोपहर के बिचारे ओहरो ओहरो क्वट फंडिंग नही हलें।
सिक्कुर के बिचारे ओहरो ओहरो क्वट फंडिंग नही हलें।
मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।
नही हलें।

कल यहाँ एक करोड़ और पाँच करोड़ की बहस चल रही थी लेकिन क्वट फंडिंग नही हलें।
मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।
मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।
मैंने क्वट फंडिंग नही हलें।

میں کہتے ہیں کہ اگر مندرجہ بالا دو قسمی سیریس ہیں اور ایک نازک اور
 تو ایسی چیک سرکس گیش کے ذریعہ چیک سیکلز میں آدی بھیجے جائیں گے
 اپنے پارلیمنٹری زندگی میں کوئی ایک منسٹر دیکھا جس نے کوئی ایسی کا منسٹر کی
 بات کو قبول کیا ہر طرف ایک منسٹر منسٹر صاحب کو میں نے دیکھا جس نے ایسا
 کیا ہے۔ ہمارے ڈپٹی پرائمر منسٹر کو ہی دیکھئے۔ کتنی ہی قبول! ت کیوں نہ ہو
 نائز پر سٹیج میں بیٹھ کر وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ میں شری ہینٹ کو کا گٹر پکچر
 کرتا ہوں کہ وہ کہہ لیں کہ بھلائی کی بات کرتے جارہے ہیں۔ یہ بات ان کی
 قابل تخریف ہے لیکن میں ان سے کرلیٹ کرتا ہوں کہ جیسے پہلے ہوتا آوا
 ہے اگر آپ کہ وہی ہوا تو اس کا نتیجہ خراب ہونے والا ہے۔ میں امید کرتا
 ہوں کہ جہاں تک سٹیج کا سوال ہے اس پر منسٹر صاحب فرور تو جہاں گے
 اور ان کا منسٹر کرتے وقت خوب ٹھونکے بغیر ان کو کیا جائیگا۔ جرمی کسٹون
 کے تیش ہوں وہ اس کا رولر سٹیشن کو چلا لیں اور زر رو بیگ کو میں چلا لیں
 میں دو تیس دن کے اندر دوسرا آئی اور بیڑنے والا ہوں میرے ہر ایک
 سرکاری آئینے نہیں کھلیں قراب کھل جائیں گی۔

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के लिये सरकार को हादिक बधाई देता हूँ कि सरकार को देर से ही सही, लेकिन यह बात सूची कि किसानों के लिये कुछ करना चाहिये, खास कर उन किसानों के लिये जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के हैं जहाँ पर कोम्पारेटिव कमजोर हैं। सरकार के दिमाग में यह बात बहुत देर से आई कि इन स्टेट्स में कोम्पारेटिव कमजोर है। डा० राम सुभग सिंह यहाँ बैठे हुए हंस रहे हैं लेकिन जब वह ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उन्होंने खुद सोचा कि इन जगहों पर कोम्पारेटिव कमजोर है।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसानों को रुपया देने का सवाल है तब नियम सरल होना चाहिये, नहीं तो जो कोम्पारेटिव की स्थिति है वही होगी कि किसान दीड़ते-दीड़ते मर जाता है, लेकिन कोम्पारेटिव से रुपया जल्दी नहीं मिल पाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्राप ने जो लिमिट प्राप बिजिनेस रक्की है वह बढ़ाई जाये। मैं श्री पन्त से कहना चाहता हूँ कि वह किसानों से हमदर्दी रखते हैं तो कम से कम जो बिजिनेस की लिमिट है उस को बढ़ायें। मैं एक कोम्पारेटिव बैंक का मेम्बर

हूँ। उस में लिमिट इतनी कम रहती है कि जब पैसा चुक जाता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

स्टेट में तो कोम्पारेटिव होंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेंट्रल स्टेट ऐग्रीकल्चर क्रेडिट कारपोरेशन भी होना चाहिये ताकि सब कोम्पारेटिव का भन्दाज रहे कि कहां कितना बिजनेस हुआ और कितना नहीं हुआ। इस की सख्त जरूरत है जिस की गुजाइस इस बिल में नहीं रक्की गई है। प्रागे सरकार इस पर विचार करे और सोचे।

जब प्राज इस कारपोरेशन की स्थापना होने जा रही है तब इस में ऐसे अफसर रक्खें जायें जो किसान-माइन्ड हों और किसानों की कठिनाई को सोचते हों। किसान को कब किस प्रकार की जरूरत है उन को मालूम होना चाहिये। अगर प्राप शहरों के लोगों को वहाँ पर रख देगे तो उन को तो पता ही नहीं होगा कि कब भदई की फसल होती है, कब रबी की फसल होती है और कब अगहनी की फसल होती है और कब किसान को रुपयों की जरूरत होती है कब नहीं। इस विभाग में जो बड़े-बड़े अफसर रक्खे जायें वरु किसान-माइन्ड हों और गांवों से प्राणे वाले हों, जिन के घर का वे प्राप लाइफ किसानी का हो। भले ही वह शहर में रहते हों, लेकिन इस संगठन में वे ही लोग रहें जो किसान के दुःख दर्द को समझते हों। अगर वसा प्रादमी नहीं रक्खा जायेगा और शहर का प्रादमी रक्खा जायेगा तो उसे किसान से कोई मतलब नहीं होगा।

इस के साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि किसान से कर्ज को वापस लेने की धारा में जो पांच वर्ष का समय रक्खा गया है उस में कुछ सुधार हो। मान लीजिये किसी किसान ने ट्रक्टर खरीदा। तो पांच वर्ष में ट्रक्टर से खेती कर के जो उस की प्रादमी होगी उस से वह अपना कर्ज नहीं अदा कर पायेगा। मेरा अफना भन्दाज है कि पांच वर्ष का जो नियम रक्खा गया है उस को बढ़ा कर दस वर्ष रक्खा जाये ताकि दस वर्ष में अगर वह कोई अड़ा

[श्री विभूति मिश्र]

काम करना चाहता है, कोई बाँध बनवाना चाहता है, कोई बड़ा कुआँ खुदवाना चाहता है, बिजली लगवाना चाहता है या बिजली के लिये टैंक बनवाना चाहता है तो वह उस काम को भासानी से कर सके और कर्जा भी भ्रदा कर सके ।

मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज को जल्दी से जल्दी लागू करे और जिन स्टेटों में कोऑपरेटिव कमजोर हैं, जिन के लिये यह खास तौर पर बनाया जा रहा है, उन की ओर इस में विशेष ध्यान दिया जाये । ऐसा न हो कि इस की स्थिति भी कोऑपरेटिव जैसी हो, जिस के बनाने से कोई फायदा न हो ।

श्री महाराज सिंह भारती (भिरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को कर्ज देने वाली बहुत सी एजेन्सियाँ पहले से यहाँ चल रही थीं, यह भी एक नई एजेन्सी बनाई गई है । मालूम तो ऐसा पड़ता है कि बहुत ज्यादा कर्जा देने के लिये सरकार लालायित है, लेकिन दो कसौटियाँ कर्जा देने की होती हैं । दोनों में ही यह नई एजेन्सी बनने के बाद कोई राहत मिलने वाली नहीं है । पहली कसौटी यह है कि चूँकि राष्ट्रीय धाय का पचास फीसदी से ज्यादा भाग खेती से आता है और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस का भी 50 फीसदी से ज्यादा भाग डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली खेती से ही आता है, इस लिये मुल्क का जो फाइनेन्शाल क्रेडिट सिस्टम है उस में 50 प्रतिशत कर्जा खेती को दिया जाना चाहिये । लेकिन मुसीबत यह है कि खेती का जो विषय है वह सूबे का है और रुपये पैसे की मालिक दिल्ली की सरकार है । बैंक सारे धाय लोगों के हाथ में हैं । शायद धायका ताल मेल नहीं बैठता और बीच में फजीहता हो जाया करता है । कर्जा जो बैंक सोशलसाइजेशन सिस्टम चलाया गया उस में से 18 प्रतिशत कर्जा धाय खेती के लिये देते । उस 18 प्रतिशत में से भी धाय देखेंगे कि 10-12 प्रतिशत ट्रेड ले जायेगा खेती के लिये से । मैं कहना चाहता हूँ कि इस कसौटी

पर अब तक जितनी धाय की एजेन्सीज हैं सब मिल कर सिवा इस के कि किसानों को मूर्ख बनायें और कुछ नहीं करतीं । प्रोपेगेन्डा के लिये तो धाय कह सकते हैं कि यह एजेन्सी किसानों को कर्जा देने के लिये और दूसरी सहुलियतें देने के लिये हैं, लेकिन सही बात यह है कि इस मुल्क में कर्जा देने के लिये जो फाइनेन्सिंग होती है उस का 50 प्रतिशत निश्चित रूप से खेती पर जाना चाहिये, लेकिन वह 10 प्रतिशत तक नहीं पहुँच रहा है । इस बिल के बाद भी वह नहीं पहुँच पायेगा ।

किसानों को कर्जा मिल जाये उन की हैसियत के हिसाब से और कर्ज की वसूली होने की गारन्टी हो, इस में कोई दो राये नहीं हो सकती । सरकार ने कभी इस बारे में नहीं सोचा । ऐसी हालत में इस तरह का बिल लाने से कोई फायदा नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार हिम्मत कर के धाय कोई ऐसा सिस्टम बना लीजिये और कोई ऐसा बिल ले आइये जिस में इन पचास एजेन्सियों के बजाय एक ही एजेन्सी रह जाय । हर किसान को यह पता हो कि उस की हैसियत क्या है । सरकार उस को एक काड्ड दे सकती है, एक पास बुक दे सकती है जिस में उस की हैसियत लिखी हुई हो । अगर वह अपनी जमीन बेचे तो उस का दाखिल खारिज हो जाये, अगर वह खेती के लिये कर्जा ले तो वह कर्जा उस में लिख लिया जाये, वह किस जगह पर है इस का उस को पता रहे । उस को मासूम रहे कि इतना रुपया वह ले सकता है और यह उस को देना है । इस के लिये धाय एजेन्सी बनायें । मान लीजिये कि मेरी हैसियत कुछ है । मैं 5,000 रु० और ले सकता हूँ । तो मैं एजेन्सी से जा कर 5,000 रु० ले लूँ । उस के बाद यह गारन्टी सूबे की सरकारों के साथ होनी चाहिये कि वह रुपया अगर मैं नहीं बेता तो वह एजेन्सी लैंड रेवेन्यू की तरह से मुक्त से ले ले । अगर मेरी जमीन इस के लिये नीलाम भी हो जाये तो भी वह रुपया मुक्त से बसूरा ही जाये, और जिसना

रुपया एजेन्सी हमें दे उतना ही रुपया रिजर्व बैंक एजेन्सी को एडवॉन्स कर दे। इस रुपये को फाइनेन्स करने के लिये एक ही एजेन्सी होनी चाहिये और वसूली की गारंटी होनी चाहिये ताकि रुपया सहूलियत से वसूल हो सके। दोनों बातों का समन्वय बहुत जरूरी है। जितनी अब तक की आप की फाइनेंसिंग एजेन्सीज हैं किसी के जरिये से इन में से कोई काम नहीं हो रहा है। यह जो एजेन्सी आप हम को दे रहे हैं इसको देने में जितना हम को फायदा होता है उससे ज्यादा हम को परेशानी हो जाती है। कौन सी आप गारंटी करेंगे कि आसानी के साथ कर्जा किसानों को मिल जाएगी। आपकी अफसरशाही है जो कि हर जगह चल रही है। कोओपरेटिव्स में वह चल रही है। यहां भी वही चलेगी। थोड़ा तो आप रुपया देंगे, ज्यादा मांगने वाले होंगे। इसकी वजह से फिर वही प्रोसीजर चलेगा। इस अफसर से उस अफसर तक चीज जाएगी। नतीजा यही होगा कि कर्जा देने वाला आदमी जो है उसको कई सौ रुपया तो रिजर्वन में देना पड़ जाएगा। उसके बाद वसूली का सवाल पैदा होता है। इस सब का क्या परिणाम निकलेगा, इसको आप भी देख सकते हैं।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था और वित्त मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हम हाउस में भी मैंने इस सुझाव को रखा था। लेकिन उसकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं उस चीज को दोहरा देना चाहता हूँ। आपने एक ही देश में दो मुस्लिम किसान और गैर किसान बना दिये हैं। किसान और गैर किसान के लिए भेदभाव आपने क्यों बरत रखा है। आपके बैंकिंग सिस्टम में लैंड मार्टगेज बैंक मौजूद हैं। वे सबों के अन्दर हैं। वहाँ से अगर किसान कर्जा लेना चाहता है तो कानूनन उसको छूट है कि वह कोर्ट फीस न दे। बिना कोर्ट फीस के उसको कर्जा मिल जाता है। लैंड मार्टगेज बैंक सबों की सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उन से पोलिटिकल फायदा भी उठाया जाता है। जिस दल की सरकार बनती है वह किसानों को कर्ज

दिलाने के नाम पर राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहती है। जो दूसरे बैंक हैं इनमें से अगर किसान कर्जा लेना चाहता है तो अठारह सैकड़ा उससे लिया जाता है। किसान लैंड मार्टगेज बैंक से जो कर्जा लेता है उसके दो साल के ब्याज के बराबर उसका खर्चा हो जाता है अगर वह दूसरे बैंकों से कर्जा लेना चाहता है तो। सोलह सतरह सैकड़ा जैसा बड़ा ब्याज हो जाता है। मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि मेहरबानी करके एक सर्व्यूलर निकाल दीजिये इसके बारे में। जहाँ पर सेंटर का राज है वहाँ तो गवर्नर से कहकर आप निकाल सकते हैं, आप अभ्यावेश जारी कर सकते हैं और जहाँ पर गवर्नर का राज नहीं है, वहाँ पर आप उनको सलाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह तो सबों का विषय है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक हजार बानों में तो आप सबों को सलाह देते रहते हैं लेकिन इस बात में आप नहीं दे सकते हैं। जहाँ आपका मतलब होता है वहाँ पर तो आप दे सकते हैं लेकिन जहाँ पर किसान के मतलब की चीज होती है तो आप सबों को राय नहीं दे सकते हैं? क्या इसका यह अर्थ लगाया जाए कि सबे किसी दूसरे देश के हिस्से हैं, उन से सेंटर का क्या मतलब? आप उनसे क्या कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं? यह तो एटीट्यूड है यह किसान और बेती के लिए निहायत ही खतरनाक एटीट्यूड है।

मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन दोनों कसौटियों पर, किसान को ऋण देने वाली बात पर यह बिल खरा नहीं उतरता है तो यह बेकार का बिल है। इससे पहले भी जितने बिल आपने बना रखे हैं, वे भी बेकार हैं। दूसरी कसौटी यह है कि राष्ट्रीय धाय का जितना बड़ा हिस्सा आप बेती से ले रहे हैं और एक्सपोर्ट में जितना बड़ा हिस्सा आप बेती से ले रहे हैं, उतना हिस्सा किसान को ऋण में आप देने की व्यवस्था करें। टोटल फाइनेंसिंग जो कृषि में होनी है, उसमें आप इसको भी शामिल करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कितनी आसानी से और बिना रिजर्व

[श्री महाराज सिंह भारती]

दिये हुए उसको ऋण मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों कसौटियों पर आपका यह बिल खरा नहीं उतरता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक कम्प्रोमिसिव बिल आप लायें, एक ही एजेंसी बनाने की कोशिश करें, जो इन सब कामों को कर सकें और जो इन दोनों कसौटियों पर खरी उतर सके।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मैं इस बिल का हादिक समर्थन करता हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू नहीं कर देना चाहिये। मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सामने बैठे हुए है ये कोई मामूली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं। बड़े बाप के ये बड़े बेटे हैं। फाइनेंस के ये पंडित हैं। ये इस चीज को जानते हैं। इनसे हम लोगों को बड़ी आशा है, विश्वास है। कर्मिंग इवेंट्स कास्ट देअर शेडो वीफोर। मुझे यकीन है कि ये बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर साहब साबित होंगे। ये पस्ट क्लास एम० ए० सी० हैं। आपकी तरह से मिडल फेल नहीं हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि पंत जी के नेतृत्व में हम गरीब किसानों को समय पर कर्जा मिल सकेगा और हम सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। जिस तरह के डपोल संखिये आपकी संविद सरकार में थे, उस तरह के इस सरकार में नहीं हैं। संविद सरकारों की डपोल संखियों जैसी नीति रही है, हमारी सरकार की नहीं रही है। हमारी जिस सरकार ने बिजली चार खम्भों तक फ्री वी थी किसानों को, इनकी गवर्नमेंट जब पावर में आई तो उसने हमारे ऊपर बँन लगा दिया। हम किसान लाख धांसू बहाते हैं, रोते हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। हम को ठीक समय पर कर्जा मिलना चाहिए। दफ्तरों में काम ठीक से होना चाहिए। अधिकारी वर्ग को ठीक तरह काम करना चाहिए। महाराज सिंह भारती जी ने जो रिक्वत वाली बात कही है, उस रिक्वत

वाले बाजार को आप ठीक करें। खेती को आप ठीक करें ताकि हम को झमरीका से भीख न मांगनी पड़े। ठीक ढंग से और ठीक समय पर कर्जा हम को मिले, खेती का डिबेलेपमेंट हो, यह हम सब की कामना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि पन्त जी के रहते हुए हमारे देश का कल्याण होगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : वैसे तो जब संशोधन पेश किये गए थे तभी मैं बोल चुका हूँ लेकिन अब जब इस बिल को पास करने जा रहे हैं, तो मैं एक बार फिर इसका स्वागत करता हूँ।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि हम ओवर-आप्टिमिस्ट हो जाएं और ओवर-आप्टिमिज्म में आ कर जो हकीकत है, उसको भूल जायें और वास्तव में जिनको इस बिल से फायदा पहुंचना चाहिए, उनको न पहुंच पाये। कर्जा देने वाली जो आपकी एजेंसीज हैं, जो सिलसिला आपने एग्रिकल्चरल लॉज का बनाया है, तकावी कर्जों का बनाया हुआ है, कोओप्रेटिव लॉज का बनाया हुआ है, उस सिलसिले को आप सरजमीन पर जा कर देखिये और पता लगाइये कि वास्तव में कितना कर्जा किसानों को मिलता है और कितनी कठिनाइयों और परेशानियों में से होकर गुजरने के बाद मिलता है। जो आपकी मशीनरी है यह भ्रष्ट मशीनरी है। यदि आपकी मंशा यह हो कि किसान को एक रुपया मिले तो वास्तव में उसको दस पैसे ही मिल पाते होंगे। यह जो बीमारी है, इसको आपको खत्म करना होगा। यह तो सभी अनुभव करते हैं कि कृषि में क्रेडिट की कमी अनुभव की जा रही है और उनको समय पर कर्जा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, पूंजी का इंतजाम नहीं हो पाता है, बीज का इंतजाम नहीं हो पाता है, दूसरी सुविधाओं का नहीं हो पाता है। इस वास्ते ये सुविधाओं उसको उपलब्ध हों इसका प्रबन्ध आप

को करना होगा। इनके अभाव में वे उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं, खेती का विकास नहीं कर पाते हैं। ये जो रुकावटें हैं इनको ध्रापको दूर करना चाहिए यदि ध्राप चाहते हैं कि वास्तव में किसान को फायदा हो और ध्रापका उत्पादन बढ़े। इसको इम्प्लेमेंट करने वाली जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें ध्रापको परिवर्तन करना होगा, उसमें ध्रापको बुनियादी तबदीलियां करनी होंगी। जब ध्रापने ऐसा किया तब जाकर यह मुमकिन होगा कि ध्रापका जो मकसद है वह पूरा हो।

क्रेडिट से ही एग्रिकल्चर का जो मसला है वह हल होने वाला नहीं है। भ्राजादी के वाद जमींदारी का एवालुशन हुआ। लेकिन इससे क्वालिटेटिव चेंज जो भ्राणा चाहिए था वह नहीं आया। ध्रभी भी बहुत से लोग हैं जो बेजमीन हैं। उनका मसला एक बुनियादी मसला है। जब तक ध्राप भूमिहीनों को जमीन नहीं देते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। क्रेडिट के लिए ध्राप जितना पैसा दे दें, दिखाने के लिए ध्राप बेशक हमें बड़े बड़े भ्राकड़े दिखा दें, लेकिन जब तक हिन्दुस्तान में भूमिहीन लोगों की समस्या हल नहीं होती है, उनको भूमि नहीं मिलती है तब तक कृषि के क्षेत्र में रेडीकल परिवर्तन नहीं होगा, बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा। देश में जितनी भूमि फालतू पड़ी हुई है वह भूमिहीनों में बाँट दी जानी चाहिये। केवल कानून के द्वारा इसका हल नहीं निकल सकता है। कानून को छोड़ कर खरा ध्रामदान का जो उसूल है उसको ध्रापको लागू करना होगा। उससे भूमिहीनों को जमीन मिल सकती है। उससे कोओप्रेसन के लिए भी रास्ता साफ होगा। लार्ज स्केल फार्मिंग भी हो सकेगा। साइंटिफिक फार्मिंग भी हो सकेगा तब यह जो क्रेडिट वाली बात है इससे वास्तव में लाभ होगा, इससे एग्रिकल्चर में जो कोओप्रेसन वाली बात है, उसको बढ़ावा मिलेगा और एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा। उस समय मार्किटबल सरप्लस भी ध्रापको मिलेगा और उससे ध्रापको इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मदद मिलेगी।

इस वास्ते मैं कहूँगा कि ध्राप ओवर-आप्टिमिस्ट न हों। मशीनरी को ध्राप स्ट्रीव

लाइन करें- ताकि किसानों को भ्रासानी से कर्ज मिल सकें।

जो कुछ भी ध्राप इस वक्त बना रहे हैं उस का मैं स्वागत करता हूँ। हकीकत में किसान को इससे लाभ हो, इस पर ध्रापको गौर करना होगा।

श्री सिंकरे (पंजम) : मैं मन्त्री महोदय का अभिनन्दन करता हूँ इस वास्ते कि यह जो विधेयक है इसको केवल मेरे जैसे निर्बलीय सदस्य द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है। सभी दलों ने इसको पुरस्कृत किया है मन्त्री महोदय ने कई एमेंडमेंट्स जो पेश हुए थे उन में से कुछ को स्वीकार भी किया है। यह खुशी की बात है। यह एक योग्य परम्परा है। इस तरह की परम्पराओं का धीरे-धीरे और भी निर्माण किया जाना चाहिये।

हम यह देख रहे हैं कि भारत में गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं और श्रीमन्त अधिक श्रीमन्त होते जा रहे हैं। गरीबों और श्रीमन्तों में जो अन्तर है, वह बहुत बढ़ने लगा है। मैं चाहता हूँ कि जो कारपोरेशन बनाया जा रहा है, इसके द्वारा इस अन्तर को और ज्यादा बढ़ावा न दिया जाए और कोशिश की जाए कि यह कम हो।

इस कारपोरेशन में कर्ज देने की जो बान कही गई है, उसके बारे में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। कितना भी एक ध्रादमी को कर्जा मिल सकता है। मैंने गोघ्रा में देखा है कि जब केन्द्र सरकार ने कमशियल बैंकों को अनुमति दी थी कि वे कृषि के लिए ऋण दे सकती हैं तब वहाँ के जो कमशियल बैंक हैं उन्होंने वहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फार्मिंग के लिए घाठ-भाठ लक्ष का कर्जा दिया है। इतना कर्जा देने की वजह से नये तरीके की जमींदारी निर्माण होने का शोका है। यह ध्रावश्यक है कि छोटे किसानों को कर्ज प्राप्त करने की पूरी सुविधा दी जाये। इस बारे में कोई लिमिट न रखने का परिणाम यह होगा कि बड़े और छोटे फार्मज में अन्तर बढ़ जायेगा और इस बिल का मौलिक, बुनियादी, हेतु पूरा नहीं होगा।

[श्री शिंदरे]

जहाँ तक चेंबरमैनशिप का सम्बन्ध है, मैंने बार-बार यह स्ट्रेस करने का प्रयत्न किया है कि चेंबरमैन का पद ऐसे लोगों को दिया जाये, पब्लिक ग्रैंडरटेकिंग में जिन की श्रद्धा है। आज सुबह श्रीर कल ही इस सदन में श्री केशवदेव मालवीय का चिक्क किया गया। जब श्री मालवीय जैसे लोग किसी पब्लिक ग्रैंडरटेकिंग के चेंबरमैन के पद पर नियुक्त किये जाते हैं, तो मेरे जैसे लोग तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की किसी विषय में श्रद्धा होती है, वही उस में सुचारु रूप से कार्य कर सकता है और उस में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि इस कारपोरेशन के चेंबरमैन के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किये जायें, जिन की इस विषय में श्रद्धा हो।

श्री भोला नाथ मास्टर (अनवर) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बिल बहुत ही अच्छे समय पर आया है। जब पंडित जी ने कम्युनिटी प्राजेक्ट और पंचायती राज का एक नया दौर शुरू किया था, उस समय यह न्याय था कि उन के द्वारा देहात का क्षेत्र विकास करेगा। लेकिन वहाँ से जो तकियाया मिलती थी, लगभग सभी सरकारों ने उन्हें खत्म कर दिया और यह काम को-ऑपरेटिव के सुपुर्द करना तय किया गया लेकिन यह देखा गया कि किसानों को न तो लैंड मार्गेज बैंक से पूरा पैसा मिला और न को-ऑपरेटिव बैंक से। को-ऑपरेटिव बैंकों में सब से बड़ी कठिनाई मीडियम टर्म लोन के बारे में है। इस लिए इस बिल में यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मीडियम टर्म लोन और लांग-टर्म लोन दिये जायें।

इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में किसी मशीनरी के लिए केवल दस परसेंट जमा कराना पड़ता है, लेकिन अब किसान ट्रैक्टर की तकाली के लिए सामुदायिक विकास बैंड में जाता है,

तो उसे पचास परसेंट जुटाना पड़ता है। उस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। मेरा सुझाव यही है कि जो सहूलियत इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दी जाती है, वही किसानों को भी दी जानी चाहिए।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह ग्राम चर्चा है कि यह सरकार बिल्कुल नानायक सरकार है, लेकिन पिछले बीस बरसों के बाद यह सुन्दर बिल ला कर इस सरकार ने जो काम किया है, मैं उस का स्वागत करता हूँ।

हम सब लोगों की यह इच्छा है कि किसानों को जो कर्जा दिया जाये, वह उन्हें बहुत सरलता से मिले और उस में कानून की इतनी पेचीदगियां नही होनी चाहिए, जिन के कारण उन्हें परेशानी हो। इस समय यह स्थिति है कि किसानों को कर्जा लेने में बड़ी दिक्कत पेश आती है और वे बहुत परेशान होते हैं।

आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है; आज वह कर्जों के बोझ से दबा जा रहा है। अगर किसानों को कर्जा सरलता से मिले और उस में कोई कानूनी पेचीदगियां न हों, तो वे उस का सदुपयोग पैदावार बढ़ाने के लिए करेंगे। अधिक पैदावार होने से हमारा देश इस आर्थिक संकट और कर्जों के बोझ से छुटकारा पा सकता है।

जो काश्तकार भूमि खरीदते हैं, उन्हें सरलता से कर्जा मिलना चाहिए इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि बनबासी, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के लोग और हरिजन इस दिशा में अधिक रुचि लें और कर्जा ले कर जमीन खरीवें और उस में अधिक पैदावार करें। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस समय जो जमीन परती पड़ी है, जो किसी के काम नहीं आ रही है, वे लोग उस में हल चला कर पैदावार को बढ़ावें।

श्री शशि भूषण बाजपेयी (खारगोन): एक लायक भ्रादमी का सर्टिफिकेट तो मिला सरकार को ।

बिल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली चर्चाओं में इस विधेयक के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बातें उठाई गईं, उनके बारे में मैं बोल चुका हूँ । जब इस विधेयक की धाराओं और संशोधनों पर विचार हुआ, तो हमें उन सब विषयों में तकमीन के साथ जाने का अवसर मिला । इसलिए इस वक्त उन सब बातों के बारे में लम्बी चर्चा करने का अवसर नहीं है । मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के सभी कोनों से इस विधेयक का समर्थन हुआ है, यहां तक कि २०, २१ साल के बाद श्री कछत्राय को भी सरकार द्वारा लाये गये किसी विधेयक का समर्थन करने का अवसर मिला ।

इस विधेयक में इस सदन की कितनी दिल-चस्पी है, यह तो इसी से स्पष्ट होता है कि इस के मिनसिने में यहां पर २०६ संशोधन पेश हुए और उनके बारे में भी यहाँ बहुत दिलचस्पी के साथ चर्चा हुई । भले ही कोई सैद्धांतिक मन-भेद इस बारे में नहीं था, फिर भी इस विधेयक पर इनकी लम्बी चर्चा हुई कि यद्यपि इसके लिए दो तीन घंटे दिये गये थे, लेकिन यह छः मान, आठ घंटे तक चला और इसके हर एक पहलू और इस बिल के बाहर भी जा कर सारी कृषि-नीति और अन्य सम्बद्ध विषयों पर चर्चा हुई ।

माननीय सदस्य, श्री शिकरे, ने मेरे बारे में प्रश्न जो कहा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ । उन्होंने कई संशोधन स्वीकार किये जाने के बारे में कहा । यह तो हमारा काम ही है । संसद् में विधेयक इसी लिए आता है कि उसमें सुधार करने के लिए मुझाबों और संशोधनों को गया-सम्भव स्वीकार किया जाय ।

श्री अशुल गुनी डार : लेकिन हमने यह भीका पहली बार देखा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि

उन्होंने इस विधेयक में इतनी दिलचस्पी ली और प्रत्ययन कर के अपने-अपने संशोधन और सुझाव दिये ।

इस चर्चा से एक बात तो यह निकली कि कृषि-उत्पादन के विषय में सब की चिन्ता है और सब चाहते हैं कि हम खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता की तरफ बढ़ें । माननीय सदस्य, श्री भारती, ने एक ही एजेन्सी बनाने का सुझाव दिया । मैं समझता हूँ कि एक एजेन्सी से काम चलना बड़ा मुश्किल है । वह खुद कहते हैं कि ऋण की मात्रा, उसका अनुपात, बढ़ाने की आवश्यकता है । अगर एक ही एजेन्सी रखी जाये, तो यह संभव नहीं है । इसके लिए कई एजेन्सीज की आवश्यकता हो सकती है । वह चाहेंगे कि इस काम के लिए बैंक भी कर्ज दें और को-ऑपरेटिज्ज भी । दो एजेन्सीज तो ये हैं । यह कारपोरेशन एक तीसरी एजेन्सी है । इस लिए मैं समझता हूँ कि वह इस बात को मानेंगे कि एक ही एजेन्सी बनाना इतना सरल नहीं है और उस से गायद किसानों को पूरा लाभ भी नहीं हो पायेगा ।

किसी माननीय सदस्य ने इस बात पर तो एतराज नहीं किया कि सहाकारिता के ही द्वारा किसान को कर्ज पहुंचाया जाना चाहिये, लेकिन इस बात की चर्चा प्रवृत्त की गई कि कई जगहों में सहाकारी संस्थाएँ प्रकृष्टी तरङ्ग ने नहीं बन रही हैं, उन में कुछ खासियाँ और कम-जोरियाँ हैं । श्री भा और श्री डार ने इसकी चर्चा की । मैं उन माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब सहाकारी संस्थाएँ राज्य सरकारों के नीचे काम करनी हैं । एक हद तक उन से मनाह-मसबरा तो हो सकता है, लेकिन प्राब्लर में यह काम राज्य सरकारों के नीचे ही आता है । इसलिये जिस-जिस राज्य से वे आते हैं, अगर वे वहां की सरकारों को सलाह दें, तो ज्यादा लाभ होगा । मुझे बड़ी आशा है कि अब राज्य सरकारों जल्दी से जल्दी इन कारपोरेशनों का संगठन करेगी ।

एक चीज की चर्चा फिर इस वक्त हुई । मैं उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ । वह यह कि इसका पैसा कम होगा और

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

इस में जितना पैसा रखा गया है वह पर्याप्त नहीं होगा ऋण देने के कार्य को पूरा करने के लिए सारी बहस में मैं नहीं जाता। लेकिन यह मैं प्रायबासन दे सकता हूँ सदन को कि अगर यह पैसा पर्याप्त नहीं है, जिस काम के लिये रखा गया है उसके लिये काफी नहीं है तो हम प्राप के पास प्रायोगे और पैसा बढ़ाने की आवश्यकता समझेंगे तो उसको बढ़ायेंगे। इस लिए इसके बारे में प्राप को कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

शिकरे साहब ने दो एक बातें कही थीं। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात थी कि लिमिट रहनी चाहिये। यह बिल में रखने की बात नहीं है। यह बाद को बोर्ड के तय करने की बात है।

कोर्ट फीस का जिक्र भारती जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट फीस प्राप कहते हैं कि राज्य सरकारों की बात है। तो राज्य सरकारों की बात तो है ही। यह स्टाम्प एक्ट के मातहत राज्य सरकारें कोर्ट फीस मुकरंर करती हैं।

श्री महाराज सिंह भारती : प्राप उनको सलाह दे सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम उनको लिलेंगे। प्राप को पत्र उप-प्रधान मंत्री ने लिखा है, वह मिला होगा।

श्री महाराज सिंह भारती : नहीं मिला है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ताज्जुब है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ी तो लिलेंगे।

श्री महाराज सिंह भारती : अभी आवश्यकता पड़ी नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्राप यह पत्र पढ़ लें फिर सलाह देना चाहें तो दें करना सदन का समय खराब होगा।

तो मैं आखिर में फिर सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी दिल-चस्पी उन्होंने इसमें ली और प्राप्ता करता हूँ सदन इस बिल को पास करेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the question is :

"That the Bill, as amended be passed."

The motion was adopted

14.40 hrs.

MOTION RE FINAL REPORT OF
ROAD TRANSPORT TAXA-
TION ENQUIRY COM-
MITTEE—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up further consideration of the Final Report of the Road Transport Taxation Enquiry Committee. The time at our disposal is 1 hour and 20 minutes. I do not like that this be discussed in instalments. The House would like to hear the hon. Minister. I would request the hon. Members to confine their remarks to 10 minutes each. Shri Goel to continue his speech. You have already taken 10 minutes. Please conclude in a few minutes.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I narrated yesterday that the transport industry is in the doldrums. It has not got a fair deal at the hands of the Government. It is good that the hon. Minister is present today. We missed him very much yesterday. He himself is of the opinion that, at present, the industry is faced with several difficulties. I would not read from his speech where he has admitted all this. He has admitted that the industry is suffering from heavy taxation. I would like to make an appeal to him that, if he really feels that the industry is suffering from heavy taxation, that it will be good to make a beginning with the reduction of excise duties on fuel, tyres and tubes and vehicles so that this burden may be reduced to some extent.